यूपीआई ने रचा नया वैश्विक कीर्तिमान

इंटरऑपरेबिलिटी ने बढ़ाया यूजर एक्सपीरियंस

जून 2025 में 32त्न लेनदेन वृद्धि दर्ज

नई दिल्ली,11 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस के व्यापक उपयोग के कारण भारत अब तेज भुगतान के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है. 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से, यूपीआई में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जबकि नकद उपयोग के कई संकेतकों में गिरावट आई है.

आईएमएफ ने अपने पेपर ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स- द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी में कहा कि यूपीआई अब प्रति माह 18 बिलियन से अधिक लेनदेन संसाधित करता है, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी है.

आईएमएफ ने जोर दिया कि इंटरऑपरेबिलिटी ने उपयोगकर्ता अनुभव को काफी बढ़ाया है और डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने में मदद की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटर ऑपरेबिलिटी उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा ऐप चुनने की स्वतंत्रता देती है, जिससे वे उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ऐप्स का पूरा लाभ उठा सकते हैं. यह नए प्रदाताओं के प्रवेश को भी सुगम बना सकती है और मौजूदा प्रदाताओं को अपने ऐप्स को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं.

> आईएमएफ ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र समन्वय विफलताओं को दूर करने में मदद कर सकता है - जैसे सीमित उच्च-गुणवत्ता वाले ऐप्स के कारण उपयोगकर्ता को अपनाने की कमी, और कम उपयोगकर्ता को अपनाने के कारण उच्च-गुणवत्ता वाले ऐप्स की कमी - इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र को शुरू कर सकता है. प्रदर्शन के संदर्भ में, जून 2025 में यूपीआई की मात्रा में साल-दर-साल 32% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लेनदेन मूल्यों में पिछले साल जून की तुलना में 20% की वृद्धि हुई. जून में दैनिक यूपीआई लेनदेन की संख्या बढ़कर 613 मिलियन हो गई, जो मई में 602 मिलियन थी.

आईएमएफ ने बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी न केवल उपयोगकर्ता को अपनाने को बढ़ावा देती है, बल्कि बंद-लूप सिस्टम की तुलना में डिजिटल भुगतान को अधिक आकर्षक बनाती है, जहां भुगतान एक ही प्रदाता के नेटवर्क तक सीमित होते हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इंटरऑपरेबल सिस्टम के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना या विनियमन के माध्यम से उनका समर्थन करना उन देशों के लिए एक आशाजनक रणनीति हो सकती है जो नकद-आधारित से डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव करना चाहते हैं.

जापान के बाजार में भारत की दस्तक

चीन की घटती हिस्सेदारी से भारत को निर्यात का मौका

नयी दिल्ली, 11 जुलाई. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने शुक्रवार को कहा कि जापान को सिले-सिलाए कपड़ों के सबसे बड़े निर्यातक चीन की घटती हिस्सेदारी के कारण जो कमी आई है, भारत में उसे पूरा करने की क्षमता है.

एईपीसी ने कहा कि परिषद प्रमुख जापानी ब्रांड और खुदरा श्रृंखलाओं के साथ मिलकर निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के अवसरों का पता लगाने के लिए टोक्यो में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही है.यह प्रतिनिधिमंडल 15-17 जुलाई तक टोक्यो में आयोजित होने वाले मेले 'इंडिया टेक्स ट्रेंड फेयर' में भाग लेगा. भारत के 150 से अधिक परिधान निर्यातक इस मेले में घरेलू परिधान उत्पादों की विविध पेशकश प्रदर्शित करने के लिए भाग लेंगे.

> एईपीसी के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने कहा, परिषद एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को टोक्यो ले जाएगी, ताकि शीर्ष जापानी ब्रांड और खुदरा श्रृंखलाओं के साथ गहन संपर्क स्थापित करके व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके .सेखरी ने कहा कि जापानी बाजार के साथ गहन जुड़ाव के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का अधिक उपयोग हुआ है .

फॉक्सकॉन के 300 कर्मचारी लौटे

सरकारी सूत्र बोले- आईफोन उत्पादन पर नहीं पड़ेगा असर

उत्पादन जारी रखने की जिम्मेदारी एप्पल की

नई दिल्ली, 11 जुलाई. फॉक्सकॉन इंडिया के कारखाने से चीनी कर्मचारियों की वापसी, जहां एप्पल आईफोन का निर्माण होता है, का भारत में मोबाइल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह वास्तव में भारत के लिए एक अवसर है.

अधिकारी ने बताया, मैं इसे एक अवसर के रूप में देखूंगा. यदि कर्मचारी वापस जाना चाहते हैं, तो यह कंपनी और कर्मचारियों के बीच का मामला है. उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करनी होगी कि काम जारी रहे - उत्पादन प्रभावित नहीं होगा. हमने उनके वीजा की सुविधा दी. अधिकारी ने आगे कहा, जहां तक एप्पल का सवाल है, उनके पास विकल्प हैं. यह सुनिश्चित करना एप्पल की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि निर्माता उत्पादन को प्रभावित न करे.पिछले हफ्ते की रिपोर्टों के अनुसार, 300 से अधिक चीनी कर्मचारी फॉक्सकॉन के दक्षिण भारत के संयंत्रों से वापस चले गए हैं.

भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में मंदी के संकेत

सेक्टर का मूल्यांकन क्षेत्रीय तुलना में महंगा

निचले उपयोगकर्ताओं पर टैरिफ दबाव संभव

नई दिल्ली, 11 जुलाई. वैश्विक निवेश बैंक यूबीएस ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए सतर्क दृष्टिकोण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह क्षेत्र ठहराव के चरण में प्रवेश कर रहा है. यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार क्षेत्र में निकट अवधि के उत्प्रेरकों की कमी है और इसका मूल्यांकन अत्यधिक है, जिससे वृद्धि की उम्मीदें वास्तविक बाजार गतिशीलता से अधिक हो सकती हैं.

यूबीएस ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2026 के अंत में 10-12 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन इसमें देरी की संभावना अधिक है. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय मोबाइल टैरिफ अब अन्य उभरते बाजारों के अनुरूप हैं, और प्रति व्यक्ति जीडीपी के सापेक्ष प्रवेश-स्तर की योजनाएं पहले से ही उच्च स्तर पर हैं. यह ऑपरेटरों की कीमतों में और वृद्धि करने की क्षमता को सीमित कर सकता है, खासकर निचले स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए, जिससे समग्र राजस्व वृद्धि बाधित होगी.

आगामी तिमाही में मामूली राजस्व वृद्धि और कमजोर परिचालन गति की उम्मीद है. ग्राहक वृद्धि कमजोर रहने की संभावना है, और प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में कोई भी सुधार क्रमिक होगा. यह वित्तीय प्रदर्शन में सीमित वृद्धि का सुझाव देता है, जब तक कि महत्वपूर्ण रणनीतिक परिवर्तन नहीं होते.

> यूबीएस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्षेत्र का मूल्यांकन महंगा हो गया है, खासकर क्षेत्रीय समकक्षों की तुलना में . नकदी उत्पादन में सुधार के बावजूद, क्षेत्र में लाभांश भुगतान वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में कम बना हुआ है, जिससे यह आय-चाहने वाले निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है .

भारत की आर्थिक वृद्धि पटरी पर : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 11 जुलाई. बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि पटरी पर बनी हुई है. सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में प्रमुख उच्च-आवृत्ति संकेतकों में सुधार से समर्थन मिल रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में खपत में पिछली तिमाही की तुलना में तेजी आई है. स्टील की खपत में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक आयात में बढ़ोतरी और केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में वृद्धि ने मांग में उछाल में योगदान दिया है. सेवा क्षेत्र की गतिविधि में भी सुधार के संकेत दिखे, जो मजबूत सेवा पीएमआई आंकड़ों, उच्च वाहन पंजीकरण, राज्यों द्वारा मजबूत राजस्व संग्रह और ई-वे बिल सृजन में वृद्धि से परिलक्षित होता है.

जून में थोक महंगाई दर में उछाल : रिपोर्ट

खाद्य महंगाई वार्षिक घटकर 0 .60 प्रतिशत रह गई

ईंधन महंगाई दर माइनस में लेकिन संकुचन धीमा

नई दिल्ली, 11 जुलाई. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में थोक मुद्रास्फीति जून 2025 में साल-दर-साल आधार पर 0.39 प्रतिशत से बढ़कर 0.80 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है. यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य, ईंधन और कोर मुद्रास्फीति में मासिक वृद्धि के कारण हुई है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि कोर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं हैं, मई में 0.86 प्रतिशत से बढ़कर जून में 1.63 प्रतिशत हो गया. यूनियन बैंक के अनुमानों के अनुसार, जून 2025 में डब्ल्यूपीआई ने मई 2025 के 0.39 प्रतिशत के निचले स्तर से वापसी की है और इसमें तेजी आई है.

हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में वार्षिक आधार पर नरमी आई है, लेकिन मासिक कीमतों में वृद्धि देखी गई. खाद्य डब्ल्यूपीआई मई के 1.72 प्रतिशत से घटकर जून में 0.60 प्रतिशत हो गया. दूसरी ओर, ईंधन मुद्रास्फीति अपस्फीति क्षेत्र में बनी रही, लेकिन संकुचन की गति धीमी हो गई. जून में ईंधन डब्ल्यूपीआई (-)1.82 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि मई में

थोक मुद्रास्फीति मध्यम रहने की संभावना

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मानसून की प्रगति के आधार पर कृषि कमोडिटी की कीमतें अनिश्चित रह सकती हैं . मौसम संबंधी व्यवधान और कृषि में आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले किसी भी भू-राजनीतिक विकास से थोक मुद्रास्फीति के लिए अल्पकालिक ऊपरी जोखिम पैदा हो सकता है . कुल मिलाकर, रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में थोक मुद्रास्फीति मध्यम रहने की संभावना है, लेकिन वैश्विक और मौसम संबंधी कारकों से संभावित जोखिमों के कारण दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है .

लूज फास्टैग पर एनएचएआई की सख्ती

फास्टैग दुरुपयोग रोकने को ब्लैकलिस्टिंग की व्यवस्था मजबूत

नई दिल्ली, 11 जुलाई. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लूज फास्टैग्स - जिन्हें आमतौर पर टैग-इन-हैंड कहा जाता है- की रिपोर्टिंग और ब्लैकलिस्टिंग के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत किया है. इसका उद्देश्य टोलिंग दक्षता बढ़ाना और फास्टैग के उपयोग की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है.

भारत में वार्षिक पास प्रणाली और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग जैसी पहलों की तैयारी के बीच, यह कदम उन फास्टैग्स के दुरुपयोग और परिचालन बाधाओं को रोकने के लिए है जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर चिपकाए नहीं जाते हैं. ऐसी प्रथाओं से लेन में भीड़, गलत चार्जबैक और क्लोज्ड-लूप सिस्टम में दुरुपयोग होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन नेटवर्क की समग्र दक्षता बाधित होती है.इस मुद्दे से निपटने के लिए, एनएचएआई ने टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतग्राहियों को एक समर्पित ईमेल आईडी के माध्यम से %लूज फास्टैग्स% की तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं. इन रिपोर्टों के आधार पर, प्राधिकरण चिन्हित टैग्स को ब्लैकलिस्ट या हॉटलिस्ट करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा.

स्थानीय बाजारों में खाद्य तेल, चावल में तेजी

नयी दिल्ली 10 जुलाई (वार्ता) विदेशी बाजारों से तेजी के संकेतों के बीच स्थानीय खाद्य तेल बाजार में गुरुवार को विभिन्न तेलों के भाव चढ़े हुये थे. दालों में सामान्य मांग-पूर्ति के बीच मिला जुला रुख देखा गया.अनाज बाजार में चावल ऊंचे भाव पर बोला गया जबकि गेहूं और गेहूं आटा के भाव थोड़े नरम रहे. गुड़ में तेजी दर्ज की गयी. स्थानीय थोक बाजार में गुरुवार को पाम ऑयल रिफाइंड में वैश्विक संकेतों से प्रति क्विंटल करीब 35 रुपया तेज हो गया. मूंगफली तेल में भी प्रति क्विंटल 14 रुपये की तेजी दर्ज की गयी.

शेयर बाजारों में गिरावट जारी

शेयरों में बिकवाली के दबाव से सेंसेक्स, निफ्टी लुढ़के

मुंबई, 11 जुलाई (वार्ता) सूचना प्रौद्योगिकी और वाहन कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली के दबाव से शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगतार तीसरे दिन जारी रहा और प्रमुख सूचकांकों में 0.83 प्रतिशत तक टूट गये.

विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उठा-पटक भरी व्यापार नीति से फैली अनिश्चितताओं के साथ-साथ भारतीय कंपनियों के हिमाही नतीजों को लेकर भी बाजार में सावधानी है. देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद घोषित तिमाही परिणाम के बाद इसके शेयर में 3.46 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गयी. एशियायी बाजारों में मिले जुले रुख का भी स्थानीय बाजार पर असर रहा.

एशियायी बाजारों में जापान के बाजार में करीब 0.19 प्रतिशत की गिरावट रही, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.30 प्रतिशत और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.46 प्रतिशत लाभ में रहा.

समाचार विशेष

बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी 39 सीटें

कई दावेदार मैदान में डटे हुए

देहरादून. उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने अपने समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. जिला पंचायत की 358 सीटों में से 39 सीटों पर भाजपा ने अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है.

बुधवार भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत में अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. बीजेपी ने जिला पंचायत की 358 में से 319 सीटों पर अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की है. 39 सीटों को छोड़ दिया है. यानी यहां पर समर्थित प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार रात जारी हुई सूची के बाद जब कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई तो उसे क्षेत्र के लोगों में असमंजस का माहौल बना रहा. लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? भाजपा ने इसे अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी बताया है. दरअसल, प्रदेश में मौजूद जिला पंचायत की 358 सीटों में से 39 सीट बीजेपी के लिए इसलिए सर दर्द बनी रही क्योंकि यहां पर भाजपा से ही कई दावेदार मैदान में डटे हुए हैं.

इन सीटों पर नहीं हुई घोषणा- पंचायत की जिन सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किये हैं उनमें चमोली की सैंजी, पिलंग, रानौ,विनायक हॉट कल्याणी, भेंटी सीटें है. पौड़ी जिले में बमराड़ी बीरोंखाल, बथेड़ थलीसैंण, टीला थलीसैंण, भरनौ थलीसैंण है. टिहरी जिले में बगलो की कांडी, हड़ियाना, पलेडी सीट है.

> **जिसमें दम है खुद जीत कर आए**
>
> कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में लेलू प्रथम, बागेश्वर में पिंगलों, चंपावत में धुरा, कानीकोट, रानीखेत में ईडा, इकरोला मोहनरी, पिलखोली, उधम सिंह नगर में भंगा, नैनीताल में ककोड़, बडोन, सूपी, चापड़, बज्जीबंगर में भी बीजेपी ने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है . उदाहरण के तौर पर अगर टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली बंगलो की कांडी सीट की बात करें तो यहां भाजपा को सीट खाली छोड़नी पड़ी है . यहां बीजेपी के कई मजबूत कार्यकर्ता एक साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं .

भाजपा से निलंबन, शिंदे शिवसेना में एंट्री

अमरावती. भाजपा से निलंबित पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता मंगलवार को शिवसेना में शामिल हो गए. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में प्रवेश समारोह आयोजित किया गया.

गुप्ता पिछले साल भाजपा से अलग हो गए थे और अमरावती विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़े थे. गुप्ता ने 1990 में भाजपा के टिकट पर अमरावती विधानसभा का चुनाव लड़ा. इस चुनाव में जीत के बाद उन्हें मंत्री पद मिला. उन्हें अमरावती का पालकमंत्री भी बनाया गया.

इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के डॉ. सुनील देशमुख ने उन्हें हरा दिया. लेकिन गुप्ता विधान परिषद का चुनाव जीतकर विधायक बन गए. वह स्थानीय निकाय क्षेत्र से 12 साल तक विधायक रहे. इस दौरान उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. लेकिन कुछ साल पहले उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कर लिया गया.

अति पिछड़ी जाति में सेंध लगाने 'नायिका' गढ़ रहा राजद

पटना. विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजद ने इस बार अति पिछड़ी जातियों पर दांव खेला है. इसलिए राजद अपनी पार्टी के अति पिछड़ी जाति के नेताओं को नये अंदाज में उभार रहा है.

इस दिशा में उसने गोटियां फिट करना शुरू कर दिया है. इस संदर्भ में दिलचस्प और नया तथ्य यह है कि अति पिछड़ी जातियों में उभारे जा रहे नेतृत्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्हें इन जातियों में 'नायिका' की तरह गढ़ा जा रहा है. राजद के सियासी गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार अति पिछड़ी जातियों को तुलनात्मक रूप में अधिक सीटें मिलेंगी. हालांकि अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि अति पिछड़ी जातियों में उसे अति पिछड़ा में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश होगी.

दिग्गजों को हाशिये पर रख सियासी मंचों पर दी जा रही ताकत- सियासी जानकारों के अनुसार हालिया राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में मंच पर अति पिछड़ी जातियों को अधिकतम स्थान मिले.

विशेष | **पीके की कांग्रेस के ही सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश**

कांग्रेस की जगह लेने की लड़ाई

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी के नेता मान रहे हैं कि पार्टी का सबसे बुरा दौर गुजर गया है. अब पार्टी वापसी के रास्ते पर है. सबसे बुरे दौर का मतलब 2014 से 2024 का था, जब दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस क्रमश: 44 और 52 सीटों पर जीती थी और नेता प्रतिपक्ष का पद भी उसे नहीं मिल पाया था.

उस दौर में कांग्रेस लगातार राज्यों में भी हारती रही. उसकी सरकारें गिरती रहीं और उसके नेता पार्टी छोड़ कर जाते रहे. इस दौर में पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी की छवि को लेकर छवि का संकट भी चलता रहा. इस लिहाज से पार्टी के नेता मान रहे हैं कि पिछले एक साल में सब कुछ ठीक हुआ है. कांग्रेस के सांसदों की संख्या एक सौ पहुंच गई है. सोशल मीडिया के इकोसिस्टम ने राहुल की छवि को बेहतर किया है और अब राहुल गांधी एजेंडा तय करते दिख रहे हैं. इसके बावजूद कांग्रेस की जगह लेने की लड़ाई नहीं थम रही है, बल्कि तेज होती जा रही है.

कांग्रेस के पुराने नेता भी मान रहे हैं कि अगर बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चुनाव जीत गई तो वे कांग्रेस की जगह लेने की राजनीति करेंगे? असल में प्रशांत किशोर ने सबसे पहले कांग्रेस को ही टेकओवर करने का प्रयास किया था. वे सोनिया और राहुल गांधी से कई बार मिले और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने कई प्रेजेंटेशन दिए. वे चाह रहे थे कि उनको कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए. वे यह भी मानते हैं कि कांग्रेस जिस आइडिया की राजनीति करती है उसके लिए भारत में जगह है. जब कांग्रेस के नेताओं ने उनकी योजना को पंक्चर किया तो वे अकेले राजनीति करने उतरे और प्रयोग के लिए उन्होंने अपनी जन्मभूमि बिहार को चुना.

बिहार में वे पलायन, गरीबी, पिछड़ेपन, अशिक्षा आदि का मुद्दा बना कर राजनीति कर रहे हैं लेकिन वे वही सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी कांग्रेस ने गढ़ा था. वे ब्राह्मण होने की वजह से सवर्ण वोट साथ आने की संभावना देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर सवर्ण खास कर ब्राह्मण उनके साथ आए तो मुस्लिम भी आएंगे और तब दलित भी जुड़ेंगे. तभी कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि अगर वे बिहार में कामयाब हुए तो इस फॉर्मूले पर वे देश भर में राजनीति करेंगे और कांग्रेस की जगह लेने का प्रयास करेंगे.

> **इसी लाइन को केजरीवाल-ममता भी आगे बढ़ा रहे**
>
> प्रशांत किशोर से पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की जगह लेने की राजनीति शुरू की थी और गुजरात की एक विसावदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत के बाद उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया है कि जनता को कांग्रेस की जरुरत नहीं है . जनता कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है . वे दावा कर रहे हैं कि भाजपा गुजरात में 30 साल से राज इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस उसकी मदद कर रही है .

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, ए-2/2, एम.आय.जी. महानंदा नगर, उज्जैन (म.प्र.)

E-mail : mpphcl_ujjain@yahoo.in, मोबा. : 9406808103

क्र.1024 /पय/मप्रपुआअविनि/25/उज्जैन दिनांक : 10.07.2025

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 10/2025-26

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा क्रमांक-10/2025-26 दिनांक 10.07.2025 के अंतर्गत जिला उज्जैन में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2025_MPPHC_436252, 2025_MPPHC_436254 (कुल 2 निविदा) आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 24.07.2025 17.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal: **https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/121035/2025 **परियोजना यंत्री**